भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2030

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

हरित गलियारों का विकास

2030. श्री उत्कर्ष वर्मा मधुरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार जैव विविधता की रक्षा करने और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं को बढ़ावा देने के लिए शहरों में हरित गलियारों को विकसित करने की कोई योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) हरित गलियारों वाले शहरों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), भारत सरकार ने शहरी तथा क्षेत्रीय विकास योजना निरुपण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जारी किया है। (https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf)। यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देश 2014 का अध्याय - 5 "शहरी नियोजन दृष्टिकोण" हरित शहर से संबंधित है।

अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा अमृत 2.0 के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने हरित स्थलों एवं पार्कों के विकास हेतु परियोजनाएँ शुरू की हैं। अमृत के अंतर्गत, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 1606.31 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,529 पार्क परियोजनाएँ शुरू की हैं और अब तक 5,271 एकड़ हरित स्थल विकसित किए जा चुके हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अब तक 1,089.31 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 1669 पार्क परियोजनाओं को अनुमोदित किया जा चुका है, ये परियोजनाएं

13,707.64 एकड़ हरित स्थल को कवर करती हैं। अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत पार्क परियोजनाओं का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक- I में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, अमृत परियोजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक पैदल यात्रियों के लिए गैर-मोटर चालित परिवहन सुविधाओं का निर्माण करना था। अमृत के अंतर्गत 430 किलोमीटर पैदल पथ तथा 43 किलोमीटर समर्पित साइकिल ट्रैक विकसित किए जा चुके हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन के एक उप-घटक, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (सीआईटीआईआईएस) 1.0 कार्यक्रम के अंतर्गत, कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में एक ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर विकसित किया गया है। इस परियोजना के लिए हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को 115.68 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। यह परियोजना शहर के 9.25 किलोमीटर लंबे जल निकासी चैनल, उन्कल नाले के पुनरुद्धार पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य इसे वर्षा जल निकासी के स्थान पर इसे एक विकसित, समग्र सामुदायिक स्थान में बदलना है। इस कॉरिडोर के विकास से उन्कल नाले से गुजरने वाली शहर की प्रमुख सड़कों को ग्रीन कॉरिडोर परियोजना से जोड़ने का अवसर भी मिलता है, जिससे शहर में गैर-मोटर चालित परिवहन (एनएमटी) कॉरिडोर का एक नेटवर्क तैयार होता है।

*****

"हरित गलियारों का विकास" के संबंध में 11.12.2025 को लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या †2030 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक-I

अमृत और अमृत 2.0 के अंतर्गत पार्कों तथा हरित स्थलों के विकास के लिए अनुमोदित परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (20.11.2025 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अमृत के तहत शुरू की गई परियोजनाएँ		अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित परियोजनाएँ	
		सं.	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	सं.	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	0.27	-	-
2	आंध्र प्रदेश	99	80.49	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	2	2.82	8	3.43
4	असम	13	15.98	-	-
5	बिहार	25	31.10	18	41.41
6	चंडीगढ़	3	1.34	-	-
7	छत्तीसगढ	194	33.15	9	34.76
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	2	4.19	-	-
9	दिल्ली	7	14.96	9	24.31
10	गोवा	2	3.26	1	1.83
11	गुजरात	124	98.23	131	117.86
12	हरियाणा	33	42.20	-	-
13	हिमाचल प्रदेश	9	7.60	11	2.80
14	जम्मू और कश्मीर	14	24.94	-	-
15	झारखंड	35	29.38	25	30.20
16	कर्नाटक	181	112.91	229	141.79
17	केरल	78	48.65	73	41.08
18	लद्दाख	6	6.52	2	5.96
19	लक्षद्वीप	3	0.08	-	-
20	मध्य प्रदेश	111	129.50	390	129.77
21	महाराष्ट्र	128	179.13	25	189.12
22	मणिपुर	3	4.50	2	5.36
23	मेघालय	8	1.82	-	-
24	मिजोरम	4	3.49	13	0.75
25	नागालैंड	10	2.90	38	13.06

26	ओडिशा	48	40.64	-	-
27	पुदुचेरी	9	1.64	-	-
28	पंजाब	43	14.09	25	38.27
29	राजस्थान	77	54.49	3	4.33
30	सिक्किम	3	0.85	2	0.79
31	तमिलनाडु	409	232.61	565	113.65
32	तेलंगाना	35	35.69	-	-
33	त्रिपुरा	3	3.67	-	-
34	उत्तर प्रदेश	341	236.82	15	108.21
35	उत्तराखंड	44	14.73	6	6.49
36	पश्चिम बंगाल	420	91.67	69	34.07
	कुल योग	2,529	1,606.31	1,669	1,089.31

*****